जे.एस. मेहंदीरत्ता

माननीय जे.जे. संजय किशन कौल, मुख्य न्यायाधीश और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह जे.जे. समक्ष।

अभयजीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ और अन्य प्रतिवादी

2013* का सीडब्ल्यूपी नंबर *20636

18* सितंबर *2013

भारत का संविधान, *1950* - अनुच्छेद *14* और *226* - शिक्षा कानून - केंद्रीकृत प्रवेश विवरणिका सत्र *2013* - खंड बी*(आई)(2)* - राज्य कोटा सीटों के तहत मेडिकल प्रवेश - याचिकाकर्ताओं ने अपनी *10+2* शैक्षणिक योग्यता पटियाला में ली थी, जो कि है पंजाब राज्य में; चंडीगढ़ राजधानी होने के नाते - उन्होंने चंडीगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रवेश के लिए चुनौतीपूर्ण शर्त मांगी थी कि उम्मीदवार को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित स्कूल/कॉलेज से *10 + 2* परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए - माना गया कि एनईईटी- यूजी *2013* सशक्त बनाता है राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को पात्रता मानदंड निर्धारित करने होंगे - इसलिए, बिना किसी छूट या अपवाद के विशिष्ट स्थान से परीक्षा उत्तीर्ण करने/उत्तीर्ण करने के संबंध में उम्मीदवार की पात्रता के लिए विशिष्ट शर्त को चुनौती नहीं दी जा सकती है - जो याचिकाकर्ता निर्धारित परीक्षा योग्यता पूरी नहीं कर रहे थे, वे पात्र नहीं हैं प्रवेश के लिए।

माना गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर *32*, चंडीगढ़, पंजाब राज्य द्वारा स्थापित, स्वामित्व या प्रशासित और संचालित नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधीन है और चंडीगढ़ प्रशासन इसे नियंत्रित और चलाता है। केवल इसलिए कि चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है, वास्तव में उस उम्मीदवार को पात्र नहीं बनाता है जिसने पंजाब राज्य से *10+2* की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(*पैरा *11)

इसके अलावा, यह माना गया कि *NEET-UG2013* स्वयं पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को निर्धारित और शक्ति प्रदान करता है। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के छात्रों के लिए वस्तुतः कोई कोटा नहीं बचेगा क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा राज्य की राजधानी भी है और जो छात्र *10+2* उत्तीर्ण कर चुके हैं। इसी कारण और तर्क के आधार पर हरियाणा राज्य से भी चंडीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे प्रॉस्पेक्टस पर आधारित थे जैसा कि पंजाब राज्य की एमबीबीएस सीटों में प्रवेश के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए प्रचलित था और यह उन परिस्थितियों में है और उस संदर्भ में न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए गए थे। यहां उम्मीदवारों की पात्रता के लिए एक विशिष्ट शर्त है, जो उस स्थान को निर्दिष्ट करती है जहां से उम्मीदवार को बिना किसी छूट या अपवाद के अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होंगे। याचिकाकर्ता, उक्त शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर *32*, चंडीगढ़ में

एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं ठहराए जा सकते। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई और दबाई गई दलीलें और आधार कायम नहीं रह सकते, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(*पैरा *12)

याचिकाकर्ताओं के वकील मोहित गर्ग।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.

(1) इस रिट याचिका में प्रार्थना क्लॉज बी (आई) (2) को खारिज करने के लिए है प्रवेश के लिए केंद्रीकृत प्रवेश विवरणिका सत्र, 2013 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सत्र 2013 और के लिए जारी किया गया आरक्षण नीति ने 18.3.1999 को जारी किए गए पत्र को जारी किया शर्त है कि उम्मीदवार राज्य के तहत प्रवेश के लिए पात्र हो कोटा सीटों को 10 + 2 पास करना चाहिए या चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल / कॉलेज से इसकी समकक्ष परीक्षा और एक नियमित छात्र के रूप में, चंडीगढ़ में स्थित है। याचिकाकर्ताओं पटियाला में स्थित स्कूलों से अपनी 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण की है, पंजा राज्य. उनके पिता सरकार के नियमित कर्मचारी हैं पंजा के अब और पटियाला में तैनात. वे राष्ट्रीय पात्रता में दिखाई दिए2013 का सह-प्रवेश परीक्षण (अंडर ग्रेजुएट) (संक्षेप में, "NEETUG2013 ") और उसी को मंजूरी दी. वे इस प्रकार, विचार के लिए पात्र हैं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए. जारी किए गए प्रोस्पेक्टस के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा, जो आयोजित किया गया NEET-UG2013, मेडिकल कॉलेजों की कुल सीटों का 15% हिस्सा है अखिल भारतीय आधार पर भरा जाना चाहिए, जिसे 'ऑल इंडिया कोटा' कहा जाएगा'. शेष 85% सीटों पर प्रवेश पर आधारित होगा राज्य कोटा के तहत मेडिकल

कॉलेजों में सीटों का आरक्षण और निजी चिकित्सा कॉलेज के तहत प्रवेश के लिए आरक्षण 85% राज्य कोटा सीटें आरक्षण नीति के अधीन होंगी और राज्य / संघ क्षेत्र में प्रचलित पात्रता मानदंड द्वारा अधिसूचित संबंधित राज्य / संघ क्षेत्र समय-समय पर।

(2) याचिकाकर्ता, वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, आश्वासन दे रहे हैं चंडीगढ़ द्वारा प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड प्रशासन, जिसके अनुसार एमबीबीएस, यू.टी. पूल (भारतीय) सामान्य, अनुसूचित जाति से संबंधित नागरिक) शारीरिक रूप से अक्षम हैं श्रेणियों को + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनिवार्य है चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल / कॉलेज और के नियमित छात्रों के रूप में चंडीगढ़ के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है स्कूल / कॉलेज ने कहा, अन्य शर्तों के अलावा जो याचिकाकर्ता पूरा यह शर्त याचिकाकर्ताओं द्वारा जमीन पर चुनौती दी गई है वही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है ।

(3) यह याचिकाकर्ताओं के लिए वकील का विवाद है क्योंकि पटियाला में याचिकाकर्ताओं के पिता की पोस्टिंग, सरकार होने के नाते पंजाब राज्य के कर्मचारी, उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की थी पटियाला में योग्यता, जो पंजाब राज्य में है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी होने के नाते, केवल इसलिए कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र है पंजाब सरकारी कर्मचारियों के वार्डों को बाहर नहीं किया जा सकता है M.B.B.S की सीटों पर प्रवेश के लिए विचार./ B.D.S. पाठ्यक्रम जमीन पर 85% कोटा के तहत कि उन्होंने अपना 10 + 2 पास नहीं किया है नियमित आधार पर एक स्कूल / कॉलेज से योग्यता परीक्षा चंडीगढ़ में। यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च का निर्णय के मामले में कोर्ट **रामिंदर सिंह नागरा ब. जगजीत सिंह पुरी और अन्य[1],** याचिकाकर्ताओं के दावे को अपने पक्ष में शामिल करता है कहा कि एक छात्र जिसका शैक्षणिक संस्थान संघ में था चंडीगढ़ के क्षेत्र में, जबकि उनके पिता

---

[1] **(1) 2010(2) एससीटी 554**

को चंडीगढ़ में एकाउंटेंट जनरल, पंजाब के कार्यालय में तैनात किया गया था, के रूप में व्यवहार नहीं किया जा रहा था राज्य में मेडिकल कॉलेजों में सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र पंजाब की जमीन पर कि उसने योग्यता हासिल नहीं की थी पंजाब राज्य से परीक्षा के लिए पात्र ठहराया गया है चंडीगढ़ के कारण पंजाब कोटा सीटों के तहत प्रवेश, पंजाब राज्य की राजधानी होने के नाते, इसे बाहर या इलाज नहीं किया जा सकता है पंजाब राज्य के बाहर। इस समता पर, दावा किया गया है वे छात्र जिन्होंने अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की थी पंजाब राज्य, M.B.B.S में प्रवेश के लिए पात्र होगा मेडिकल कॉलेज में कोर्स, सेक्टर -32, चंडीगढ़ 85% के खिलाफ% सीटों की यू.टी. पूल.।

(4) निवेदन यह है कि याचिकाकर्ताओं के पास उन छात्रों की तुलना में बेहतर योग्यता है, जिन्हें यू.टी. पूल सीटों पर प्रवेश दिया गया है, उनके पास बेहतर अधिकार है और उन्हें केवल इस आधार पर बाहर किया जा रहा है कि उन्होंने चंडीगढ़ में स्थित एक स्कूल से अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। विवाद यह है कि योग्यता का बलिदान दिया गया है। 2012 की सिविल रिट याचिका संख्या 24747 (हरलीन चीमा बनाम पंजाब राज्य और अन्य) में इस न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर भी भरोसा किया गया है, जिसका फैसला 27.8.2013 को हुआ (अनुलग्नक पी-3), जहां पर भरोसा करते हुए रमिंदर सिंह नागराजी मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने चंडीगढ़ के एक मान्यता प्राप्त स्कूल से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, को पंजाब राज्य से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के रूप में मानने का निर्देश दिया गया था, पंजाब की राजधानी होने के नाते। याचिकाकर्ताओं के वकील ने उपरोक्त आधार पर अपनी दलीलें रखी हैं और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी केंद्रीकृत प्रवेश विवरणिका सत्र, 2013 में निर्धारित पात्रता मानदंड के खंड बी (आई) (2) को रद्द करने की प्रार्थना की है, अनुबंध पी- 2.

(5) हमने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।NEET-UG2013 का खंड 9.3 राज्य कोटा सीटों के लिए पात्रता के मानदंड बताता है, जो इस प्रकार है: -

(6) 9.3. राज्य कोटा सीटों के लिए पात्रता

(i) उसने प्रवेश के समय 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के वर्ष 31 दिसंबर को या उससे पहले आयु पूरी कर लेगा और एक भारतीय नागरिक है।

(ii) भारत के विदेशी नागरिक (ओआईसी) संबंधित राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

(7) इसके बाद खंड 11.3(ए) में राज्य कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों और निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:-

(ए) सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 85% राज्य कोटे की सीटों के तहत प्रवेश समय-समय पर संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित आरक्षण नीति और पात्रता मानदंड के अधीन होगा।

(बी) संबंधित श्रेणियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित कानूनों के अनुसार होगा।

(सी) निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की नीतियों के अधीन होगा।

(8) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि NEET-UG2013, सूचना बुलेटिन के तहत भी, प्रत्येक उम्मीदवार को विभिन्न कॉलेजों में M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए इस परीक्षा को पास करना होगा। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि 85% राज्य कोटा सीटों पर प्रवेश अधिसूचित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित आरक्षण नीति और पात्रता मानदंडों के अनुसार होगा। इससे पता चलता है कि यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अधिसूचना द्वारा अपने स्वयं के पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए खुला है।

(9) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने तदनुसार खंड बी (आई) के तहत यूटी पूल सीटों के लिए प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार है: -

के.बी. पात्रता मापदंड:

I. एमबीबीएस यू.टी. पूल (भारतीय नागरिक) सामान्य, एससी, शारीरिक विकलांगता

आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:-

1. 31 दिसंबर, 2013 को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

2. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित स्कूलों/कॉलेजों से उक्त स्कूलों/कॉलेजों के नियमित छात्र के रूप में +2 (12वीं कक्षा) की परीक्षा उत्तीर्ण की (यह शर्त सेवारत रक्षा कर्मियों/पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए लागू नहीं होती है) जिसके लिए नीचे बिंदु संख्या 4 देखें)। उसे व्यक्तिगत रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए, और पहले प्रयास में +2 स्तर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी के कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। . हालाँकि, अनुसूचित जाति के

सदस्यों के मामले में, अंकों में 10% से अधिक की छूट नहीं दी जाएगी यानी न्यूनतम 40%; शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम प्रतिशत 45% होगा।

3. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के संशोधित विनियमन के अनुसार, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड सामान्य वर्ग के लिए 50% है; भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी विषयों में योग्यता परीक्षा (+2 या समकक्ष) और प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षा (यानी एनईईटी) में अलग-अलग एससी के लिए 40% और शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवार के लिए 45%।

4. पत्र संख्या 19/1/3-आईएच(3)-2007/18322 दिनांक 14.09.2007 के माध्यम से सेवारत रक्षा कर्मियों/पूर्व सैनिकों के बच्चों के संबंध में यू.टी.चंडीगढ़ से +2 उत्तीर्ण करने की शर्त को हटा दिया गया है।

5. सीबीएसई, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एनईईटी 2013 में उत्तीर्ण और एमसीआई नियमों के न्यूनतम प्रतिशत मानदंडों को पूरा करता है। प्रवेश नीट 2013 की योग्यता के आधार पर होगा।

6. एनआरआई (विदेशी भारतीय छात्र प्रवेश) के लिए कृपया पृष्ठ संख्या 7-9(देखें।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

(10) याचिकाकर्ताओं का आधार मुख्य रूप से शर्त (2) से संबंधित है, जिसे रमिंदर सिंह नागराजी केस (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन बताया गया है, जहां एक छात्र, जिसने चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश से 10+2 कोर्स पास किया था। को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में मानने का निर्देश दिया गया था, जिसने पंजाब राज्य से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पंजाब राज्य की राजधानी होने के कारण, इसे पंजाब राज्य का हिस्सा माना जाएगा, हालांकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। उक्त सिद्धांत इसके

विपरीत भी लागू होगा। पंजाब राज्य की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ की स्थिति अलग नहीं होती है और वही रहती है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पिता कर्मचारी हैं और पटियाला में तैनात हैं, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को 10 + 2 की परीक्षा पटियाला से पढ़ने और उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर किया। उन्हें पंजाब राज्य की राजधानी के मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध सीटों के लाभ से वंचित करने का कोई अच्छा कारण नहीं हो सकता है, जब 10+2 के एक छात्र, जिसने चंडीगढ़ से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, को पंजाब राज्य से उत्तीर्ण माना गया है। . इसी तरह का लाभ उन छात्रों को दिया जाना आवश्यक है, जिन्होंने चंडीगढ़ की यू.टी. पूल कोटा सीटों के तहत प्रवेश पाने के लिए पंजाब राज्य से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

(11) याचिकाकर्ताओं की यह दलील इस तथ्य के आलोक में स्वीकार नहीं की जा सकती है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़, पंजाब राज्य द्वारा स्थापित, स्वामित्व या प्रशासित और संचालित नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधीन है और चंडीगढ़ प्रशासन उसी को नियंत्रित करता है और चलाता है। केवल इसलिए कि चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है, वास्तव में उस उम्मीदवार को पात्र नहीं बनाता है जिसने पंजाब राज्य से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। रमिंदर सिंह नागरा केस (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाला गया अनुपात उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने पंजाब राज्य से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, खासकर जब शर्तें, जो पंजाब राज्य द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित की गई थीं। अन्य शर्तों के लिए भी प्रावधान किया गया था, जिन्हें उम्मीदवारों द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक था और कुछ अपवाद भी प्रदान किए गए थे, जो यहां मामला नहीं है।

(12) इसके अलावा, NEET-UG2013 ने खुद को निर्धारित किया और राज्य / संघ क्षेत्र को शक्ति प्रदान करने के लिए अधिसूचना द्वारा शक्ति प्रदान की पात्रता मानदंड. यदि तर्क के रूप में अनुमानित किया गया है

याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, वस्तुतः कोई कोटा नहीं बचा होगा चंडीगढ़ के रूप में चंडीगढ़ के केंद्रीय क्षेत्र के छात्रों के लिए भी है हरियाणा राज्य की राजधानी और एक ही कारण और तर्क के लिए हरियाणा राज्य से अपने 10 + 2 पास करने वाले छात्र चंडीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए भी पात्र हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्णय प्रोस्पेक्टस पर आधारित थे जैसा कि M.B.B.S में प्रवेश के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए प्रचलित था। पंजाब राज्य की सीटें और यह उन परिस्थितियों में और उस में है न्यायालयों द्वारा निर्णयों का संदर्भ दिया गया। यहाँ वहाँ किया जा रहा है उम्मीदवारों की पात्रता के लिए एक विशिष्ट शर्त, जो निर्दिष्ट करती है जिस स्थान से उम्मीदवार को अपनी योग्यता को मंजूरी देनी चाहिए थी।

(13) इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा